



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2008/श्रावण 29, 1930

No. 298]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2008/SRAVANA 29, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2008

सं. 67 (आर.ई.-2008)/2004—2009

फा. सं. 01/36/218/26/एम 09/पी सी-5/  
ईपीसीजी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के  
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार,  
एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (आर ई-2008) में, निम्नलिखित  
संशोधन करते हैं :

1. सार्वजनिक सूचना सं. 26 (आर ई-2008)/2004—2009  
दिनांक 3 जून, 2008 द्वारा पैराग्राफ 5.11.3 के बाद जोड़े गए पैराग्राफ  
को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :—

“जब किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया  
जाता है, तो ऐसे निर्यात उत्पादों पर रोक/प्रतिबंध लगाने से  
पूर्व पहले से जारी ई पी सी जी प्राधिकार पत्रों के संबंध में  
निर्यात दायित्व की अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के  
रोक/प्रतिबंध की अवधि के बराबर स्वतः ही बढ़ जाएगी  
और निर्यातक को रोक/प्रतिबंध की अवधि के लिए औसत  
निर्यात दायित्व को भी पूरा करने की आवश्यकता नहीं  
होगी।”

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुज्राल; महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अफर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th August, 2008

No. 67 (RE-2008)/2004—2009

F. No. 01/36/218/26/AM 09/Pol V/EPCG-I.—In  
exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the  
Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of  
Foreign Trade hereby makes the following amendments in  
Handbook of Procedures, Vol. I (RE-2008):

1. The following paragraph added after paragraph  
5.11.3 vide Public Notice No. 26 (RE-2008)/2004—2009 dated  
3rd June, 2008 stands amended to read as under :—

“Whenever a ban/restriction is imposed on export  
of any product, export obligation period in respect  
of EPCG authorizations already issued prior to  
imposition of ban/restriction of such export  
products, would stand automatically extended for  
a period equivalent to the duration of ban/  
restriction, without any composition fee and  
exporter would not be required to fulfill average  
E.O. as well, for the ban/restriction period”.

2. This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade  
& ex-officio Addl. Secy.